Rapid Fire (करेंट अफेयर्स): 09 मार्च, 2022

ऊँट संरक्षण और विकास नीति

हाल ही में राजस्थान राज्य सरकार द्वारा बजट वर्ष 2022-23 में ऊँट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की गई है। राज्य सरकार के आँकड़ों के अनुसार राजस्थान में दो लाख से भी कम ऊँट बचे हैं। वर्ष 2012 के बाद से भारत में ऊँटों की संख्या में 1.5 लाख की कमी आई है। वर्ष 2019 में आखिरी बार गिने जाने पर लगभग 2.5 लाख ऊँट बचे थे। चूँकि ऊँटों की आबादी लगातार घट रही है, अत: राजस्थान सरकार द्वारा इस नीति की घोषणा की गई है। इस नीति के लिये 10 करोड़ रुपए का बजट भी प्रस्तावित किया गया है। इस राशि का उपयोग जानवरों की रक्षा, पालन और विकास हेतु किया जाएगा। ऊँट राजस्थान राज्य का राजकीय पशु है और इनकी संख्या लगातार घट रही है। वर्ष 2014 में राजस्थान सरकार ने ऊँट को राज्य पशु घोषित किया था। भारत के लगभग 85 प्रतिशत ऊँट राजस्थान राज्य में पाए जाते हैं जिसके बाद हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का स्थान आता है।

अटल इनोवेशन मिशन

हाल ही में नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने भारतीय युवाओं के बीच ऑगमेंटेड रियलिटी (Augmented Reality- AR) कौशल को बढ़ावा देने हेतु स्नैप इंक के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की है। स्नैप इंक एक वैश्विक कैमरा निर्माता कंपनी है। दो साल की समय-सीमा में स्नैप इंक अटल टिंकरिंग लैब्स से जुड़े 12,000 से अधिक शिक्षकों को ऑगमेंटेड रियलिटी पर प्रशिक्षण प्रदान करेगी, जिससे एटीएल के स्कूलों के नेटवर्क से संबद्ध लाखों छात्रों तक इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की पहुँच संभव हो सकेगी। स्नैप इंक द्वारा भी AR विज्ञापन बूटकैंप, विज्ञापन क्रेडिट और अन्य अवसरों सहित भारतीय स्टार्ट-अप इकोसिस्टम की मदद करने हेतु अटल इनक्यूबेशन सेंटर (Atal Incubation Centers- AICs) के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की गई। भारत में नवाचार को बढ़ावा देने के लिये नीति आयोग के कार्यक्रम अटल नवाचार मिशन के तहत अटल समुदाय नवाचार केंद्र (Atal Community Innovation Centre- ACIC) कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश के कम विकसित क्षेत्रों में सामुदायिक नवाचार को प्रोत्साहित करना है।

"पेंशन दान करें" योजना (‘Donate a Pension’ Scheme)

केंद्रीय श्रम और रोज़गार मंत्रालय ने सोमवार को **प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना** के तहत किसी भी नागरिक को एक असंगठित श्रमिक की ओर से प्रीमियम राशि का भुगतान करने की अनुमति देने वाली **"पेंशन दान करें" योजना (‘Donate a Pension’ Scheme)** शुरू की है। पेंशन योजना, जिसे वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया था, असंगठित क्षेत्र के 18 से 40 वर्ष के उन श्रमिकों, जो हर महीने 15,000 रुपए तक कमाते हैं, को उम्र के आधार पर 55 रुपए से 200 रुपए तक प्रीमियम राशि का भुगतान कर नामांकन करने की अनुमति देती है, जिसका मिलान सरकार द्वारा किया जाएगा। 60 वर्ष की आयु तक पहुँचने पर लाभार्थियों को 3,000 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी। यह योजना एक नागरिक को "अपने घर या प्रतिष्ठान में घरेलू कामगारों, ड्राइवरों, सहायकों, देखभाल करने वालों, नर्सों जैसे तत्काल सहायक कर्मचारियों के प्रीमियम योगदान को दान करने की अनुमति देती है। दात**maandhan.in के माध्यम से या कॉमन सर्विस सेंटर** पर जाकर लाभार्थी की उम्र के आधार पर 660 रुपए से 2,400 रुपए प्रतिवर्ष की राशि के साथ कम-से-कम एक वर्ष के लिये योगदान का भुगतान कर सकता है। **प्रधानमंत्री श्रम योगी** मान-धन योजना एक सरकारी योजना है जो असंगठित श्रमिकों के वृद्धावस्था संरक्षण और सामाजिक सुरक्षा के लिये है। **प्रधानमंत्री श्रम योगी** मान-धन योजना श्रम और रोज़गार मंत्रालय द्वारा प्रशासित एक **केंद्रीय क्षेत्र की योजना** है और भारतीय जीवन बीमा निगम तथा **सामुदायिक सेवा केंद्रों** (CSC) के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/rapid-fire-current-affairs-09-march-2022